

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO) | Website: www.hcta.in

Dayanand Malik

President

Mob. 9813763351

E-mail: malikdayanand03@yahoo.com

Dr. Chand Singh

General Secretary

Mob. 9354732700

E-mail: chanddav74@gmail.com

Ref. No. HCTA-01/05/20

Date 10/05/2020

For Circulation among Unit Members

आदरणीय दोस्तो नमस्कार,

आशा है कि आप व आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य बधाई के पात्र हैं जिन्होंने HCTA की अपील पर अपनी नेक कमाई से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। यह राशि अनुमानित 1.5 करोड़ रूपये बनती है। यह तभी संभव हो सका जब हम एकजुट हैं। दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है जिसकी वजह से मानवता पर संकट के बादल छाये हुए हैं। विश्व के शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्थाएं ढेर हो रही है। विकसित देशों की स्थिति ओर भी नाजुक है। एक महीने की तालाबन्दी ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। इस आर्थिक संकट की घड़ी में कुछ लोगों द्वारा प्रदेश के एडिड कॉलेजों के शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को सरकारी कॉलेजों में समायोजित व सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने की बयानबाजी की जा रही है। इस पर HCTA सख्त शब्दों में असहमति प्रकट करती है।

पीढ़ियों के अनथक संघर्षों द्वारा प्राप्त शिक्षक एकता और सेवा-लाभों पर आघात पहुंचाने की कोशिशों को एडिड कालेज शिक्षक और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

दोस्तो, पिछले चार-पांच महीनों से सेलरी की दिक्कत आ रही है। इसका कारण पिछले साल के हमारे निर्धारित सेलरी बजट में से लीव एनकैशमेंट, बढ़ी हुई ग्रैच्युटी के एरियर के भुगतान होना है।

फिर भी एचसीटीए ने वित्त विभाग के माननीय अधिकारियों से 31 मार्च को दो महीने की सेलरी के 48 करोड़ जारी करवाए।

अभी भी इस वित्त वर्ष का हमारा पारित बजट हमारे विभाग के खाते में नहीं शो हो रहा, इसलिए दो महीने की वेतन की फाईल पास होने के बावजूद सेलरी ट्रांसफर नहीं हो पा रही। चण्डीगढ़ में कर्फ्यू लगा है, हम सम्बन्धित कर्मचारियों से संपर्क में हैं ताकि दो महीने की सेलरी शीघ्र मिल सके। इसके अतिरिक्त अप्रैल व उसके बाद के महीनों के सेलरी बिल ऑनलाइन पास करवाने पर भी बातचीत हुई है जिस पर डी एच ई में कार्य किया जा रहा है।

जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले एक वर्ष से एचसीटीए वित्त विभाग व डी एच ई के सम्पर्क में रह कर वेतन डलवाने का कार्य कर रही है। जिसकी निरंतर सूचना आप सभी साथियों को भेज दी जाती है।

29 जनवरी को माननीय डी जी एच ई श्री अजित बाला जी जोशी से एचसीटीए के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई थी। जिसमें सेलरी में होने वाले विलम्ब से अवगत करवाया था। जिसके बाद सेलरी में देरी को दूर करने के लिए एडिड कॉलेजों के स्टाफ से मार्च में MIS portal भरवाए गए थे।

लॉकडाउन होने से दो दिन पहले ही एचसीटीए का प्रतिनिधि -मंडल जगाधरी में माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मैडिकल की मांग को लेकर मिला था। उन्होंने हमें दो दिन बाद चण्डीगढ़ बुलाया था। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

ऐसी स्थिति में टेक ओवर व सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष की ब्यानबाजी शुरू होती है। सरकार को एडिड कॉलेजों के शिक्षकों व गैर शिक्षकों को दो वर्ष पहले (58 वर्ष) सेवानिवृत्ति करने पर सरकार को होने वाले लाभ गिनवाए जा रहें हैं जैसे शिक्षकों व गैर शिक्षकों को दो वर्ष का वेतन, दो वर्ष की लीव एनकैशमेंट व दो वर्ष की सालाना वेतन वृद्धि का पैसा बच सकता है। यह कार्य शिक्षक व गैर शिक्षक विरोधी है।

कुछ अखबारों की कटिंग हम आपके अवलोकन के लिए भेज रहे हैं।

इनमें तथ्य या तो पूरी तरह गलत हैं या गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं।

हरियाणा कालेज टीचर्स एसोसिएशन (एचसीटीए) प्रदेश के एडिड कालेजों के शिक्षक और गैर-शिक्षक स्टाफ को सरकारी कालेजों में समायोजित करने की इस तरह की ब्यानबाजी पर सख्त शब्दों में असहमति प्रकट करती है।

वास्तव में एडिड स्टाफ को सरकारी कालेजों में टेक ओवर करने सम्बन्धी सरकार की कोई नीति है ही नहीं।

पिछली सरकार के समय डीजीएचई के अधिकारियों ने प्रबंध समितियों, प्राचार्यों व एचसीटीए से टेक ओवर सम्बन्धी राय मांगी थी। प्रबन्ध समितियों ने टेक ओवर के विचार का विरोध किया था। एचसीटीए की प्रतिक्रिया थी कि अगर सरकार स्टाफ को टेक ओवर करने का निर्णय लेती है तो सभी को सौ फीसदी संख्या में सरकारी शिक्षकों के बराबर लाभ देकर लिया जाए और पिछली सर्विस बेनिफिट का पांच फीसदी वित्तीय भार मैनेजमेंट की जगह सरकार वहन करे। लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं आया।

जो कमेटी इस मुद्दे पर बनी थी, उसकी रिपोर्ट में टेक ओवर की शर्तें थीं --- •रिटायरमेंट 58 साल।

•पिछली सर्विस बेनीफिट का पांच फीसदी मैनेजमेंट वहन करेंगी

•सरकारी कालेजों में जिस विषय का वर्कलोड नहीं है, उन विषयों के शिक्षकों को, लाइब्रेरियन को, 14 एडिड ऐजुकेशन कालेजों, अल्पसंख्यक कॉलेजों के स्टाफ को, प्राचार्यों को, हैड-क्लर्क(डिप्टी सुपर्टेंट) को टेक ओवर नहीं किया जाएगा।

टेक ओवर की मांग उठाने वाले कुछ लोग न तो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और न ही नॉन-टीचिंग स्टाफ के। अगर स्टाफ की थोड़ी बहुत भी भलाई का सोचते होते तो कम से कम उनकी मांग तो उठाते। कम से कम यह तो कहते कि सौ फीसदी स्टाफ को सरकारी शिक्षकों के समान लाभ देकर ही समायोजित किया जाए। यह भी मांग करते पिछली सर्विस का 5% वित्तीय भार सरकार वहन करे।

प्रदेश के एडिड, सरकारी कालेज व युनिवर्सिटी शिक्षक लम्बे समय से यु जी सी के अनुसार रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने व अन्य लाभ देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित तत्त्व अखबारों में ब्यान देकर इसे 58 वर्ष करने का हास्यास्पद अर्थशास्त्र बता रहे हैं।

ये लोग एडिड कालेज स्टाफ तो क्या स्वयं के भी हितैषी नहीं हैं। अगर इनके अर्थशास्त्र को मान लिया जाए तो शिक्षा पर सरकार एक भी पैसा खर्च न करे।

एचसीटीए सरकार से

- पीएचडी व एमफिल इंक्रिमेंट को मूल वेतन में मर्जर,
- एच.आर.ए. सरकारी के समकक्ष, 28 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा पर पूरे पैन्शन बेनिफिट,
- 2006 के बाद नियुक्त स्टाफ को ग्रेच्युटी लाभ,
- मैडिकल सुविधा ,
- चाइल्ड केयर लीव
- कोम्यूटेशन(commutation) ऑफ पेंशन
- नए यू जी सी रेगुलेशनज़ और समय पर सेलरी आदि

की मांग पर लगातार संघर्षरत है लेकिन ये टेक ओवर के विचारक स्टाफ की इन मांगों पर उच्च अधिकारी से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करते केवल मात्र अखबारों में बने रहने का काम करते हैं ।

एचसीटीए इन लोगों से अपील करती है कि वे अपनी शिक्षक व कर्मचारी विरोधी ब्यानबाजी बंद करें। एचसीटीए किसी भी व्यक्ति से/ व्यक्तियों से किसी भी मसले पर खुला संवाद करने के लिए सदैव तत्पर है। यह सबका अपना संगठन है, इसे मजबूत करने के लिए सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। एक बार फिर आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं ।

शिक्षक-एकता जिन्दाबाद!



प्रोफेसर दयानंद मलिक, प्रधान



डॉ चाँद सिंह, महासचिव